

बिहार विधान परिषद के लिए शून्यकाल सूचना	
श्रीमती तनवीर हसन, स०वि०प० से 162वें सत्र में दिनांक -02.07.2009 को प्राप्त शून्यकाल सूचना के संबंध में	श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना
शून्यकाल सूचना	उत्तर
<p>आज दिनांक -02.07.2009 के दैनिक हिन्दुस्तान के अनुसार वर्ष 2007 की बाढ़ में मुजफ्फरपुर जिले के 857 कच्चे मकान तथा 15523 लोगों की झोपड़ियाँ पानी में बह गई थी। मुख्यमंत्री आवास योजना से पक्का मकान बनाने का आश्वासन मिला। 2008 के बाढ़ आने से पहले हर किसी का घर बन जाए, इसके लिए जिले में विशेष जिला पदाधिकारी, श्री सी०के० अनिल की तैनाती भी हुई, पर कुछ दिनों बाद स्थिति सब जस की तस बनी रह गई। 19 मार्च 2008 को सभी बेघरों का घर बनाने हेतु जिला को रू० 69,27,00,000 का आवंटन मिला, परन्तु आज तक स्थिति वैसी ही है।</p> <p>अतः मैं सरकार से इस पूरे प्रकरण की जाँच कराकर शीघ्र बेघरों का घर बनाने हेतु सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।</p>	<p>जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के प्रतिवेदनानुसार जिला में कुल 15875 आवास निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया। 15697 लोगों को बैंक के माध्यम से राशि उपलब्ध करायी गयी। इसके विरुद्ध कुल 12205 भवन पूर्ण हो चुके हैं एवं 3492 अपूर्ण हैं।</p> <p>इस योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को 6927.75 लाख राशि उपावंटित किया गया था। जिसके विरुद्ध उनके द्वारा 3693.33 लाख का व्यय किया गया है। शेष राशि 2821.84 चालान एवं प्रत्यर्पण से जमा कर दिया गया है।</p> <p>वर्तमान में मुख्यमंत्री आवास योजना बंद कर दी गयी है।</p>

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04 / वि०स०शू०का०-119 / 2012 / / आ०प्र०, दिनांक -


प्रतिलिपि उप सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय, पटना को उनके पत्र जो भवन निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है तथा उक्त शून्यकाल सूचना जो भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से उनके पत्रांक -7549(भ०) दि०-19.09.2012 द्वारा हस्तांतरित होकर इस विभाग को प्राप्त हुआ है, के क्रम में 03(तीन) प्रतियों में / उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह० / -

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक -04 / वि०स०शू०का०-103 / 2012 /¹⁵⁴² / आ०प्र०, दिनांक - 24/4/13 =

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई०टी० मैनेजर, आ०प्र० विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव